भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 584

जिसका उत्तर 04 फरवरी, 2021 को दिया जाना है।

.....

राजस्थान में योजनाएं

584. श्रीमती रंजीता कोली:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा राजस्थान में भरतपुर और अलवर जिलों में चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त योजनाओं पर कितनी निधि खर्च की जाएगी?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क) और (ख): जल संसाधनों के विकास तथा प्रबंधन की आयोजना, वित्त पोषण, निष्पादन और रखरखाव राज्य सरकारों द्वारा अपने स्वंय के संसाधनों तथा प्राथमिकताओं के अनुसार स्वंय किया जाता है। राज्य सरकारों के प्रयासों की सहायता करने के लिए, भारत सरकार, विभिन्न स्कीमों तथा कार्यक्रमों के माध्यम से जल संसाधनों के सतत विकास और कुशल प्रबंधन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों का तकनीकी तथा वित्तीय सहायता प्रदन करती है।

केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड देश भर में भूजल प्रबंधन और विनियमन स्कीम के एक भाग के रूप में जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन (एन एक्यू यू आई एम) कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है। राजस्थान राज्य में भरतपुर और अलवर जिलों को एन ए क्यू यू आई एम कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया जा चुका है।

अटल भूजल योजना (अटल जल)-विश्व बैंक की सहायता से केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम 1 अप्रैल, 2020 से कार्यान्वित की जा रही है, जिसमें राजस्थान सहित सात राज्यों के जल की कमी वाले चिन्हित क्षेत्रों में सतत भूजल प्रबंधन के लिए समुदाय भागीदारी और मांग पक्ष संबंधी कार्यों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। राजस्थान में, यह स्कीम अलवर जिले के राजगढ़ ब्लाक सहित 17 जिलों के 38 ब्लाकों के भागों में कार्यान्वित की जा रही है। राजस्थान में स्कीम के कार्यान्वयन के लिए 1189.65 करोड रू. का अंनतिम आबंटन किया गया है जिसमें से 4.95 करोड़ रू. जारी किए गए हैं।

पेयजल और स्वच्छता विभाग, राजस्थान के भरतपुर तथा अलवर जिलों सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन-हर घर जल और स्वच्छ भारत (ग्रामीण) का कार्यान्वयन कर रहा है। इसके अतिरिक्त, जल एक राज्य विषय होने के कारण, जल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, कार्यान्वयन तथा प्रचालन एवं रखरखाव का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है, इसलिए, जिला-वार आवंटन/रिलीज इस मंत्रालय द्वारा नहीं किया जाता।

*****